केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 126 शनिवार 28 नवम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

जमीनी विवाद में युवक ने जान दिया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । नगर थाना क्षेत्र के अगई भगाड़ गांव में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट और प्रताड़ना के आरोपों के बीच एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर

मृतक की पत्नी सरोजा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति कमलेश कुमार का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद था। आरोप है कि इसी रंजिश में नामजद लोग कमलेश को अकेला पाकर आए दिन मारपीट करते थे। पत्नी के मुताबिक, लगातार मारपीट और विवाद से कमलेश मानसिक रूप से परेशान थे। शिकायत के अनुसार, कमलेश ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को शाम करीब 4 बजे घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की शिकायत पर नगर पुलिस ने उसी रात सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पुलिस ने हरिचरन, गोविन्द, ज्ञानचन्द्र, इन्द्रप्रावती, पूजा, ज्योती और कान्ती को नामजद किया है। सभी अगई भगाड़ गांव के निवासी हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत केस दर्ज किया गया है।

थाना नगर पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच उपनिरीक्षक अजय कुमार निषाद को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है।

मतदाता सूची के लिये हेल्पलाइन शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने 1950 हेल्पलाइन शुरू की है। यह सुविधा 17 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चालू रहेगी।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी एस. सुधाकरन ने बताया कि जिले के लोग मोबाइल या लैंडलाइन से 1950 पर फोन कर सकते हैं। बस्ती जिले के बाहर रहने वाले मतदाता एसटीडी कोड 05542 के साथ 05542–1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 05542–297710 लैंडलाइन नंबर भी उपलब्ध है।

हेल्पलाइन पर मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म–6, नाम हटवाने के लिए फार्म–7 और नाम–पते समेत अन्य जानकारी में संशोधन के लिए फार्म–8 भरने की प्रक्रिया बताई जाएगी। ऑनलाइन या बीएलओ के जरिए जमा आवेदनों की स्थिति भी पता की जा सकेगी।

मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदान केंद्र का नाम–पता भी हेल्पलाइन से जाना जा सकेगा। मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) मिलने में देरी, सूची में गलती और निर्वाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी मिलेगी।

कलेक्ट्रेट के ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय और सभी तहसीलों में मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां फार्म–6, 7 और 8 मुफ्त मिलेंगे। एस. सुधाकरन ने नागरिकों से मध्यम ऐप डाउनलोड करने और हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।

बुजुर्ग को अगवा कर लूटे 30 हजार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हर्रैया क्षेत्र में 70 वर्षीय भगवान दत्त को आवास दिलाने का झांसा देकर एक जालसाज बाइक पर ले गया। बस्ती में कई सीएसपी केंद्रों पर पैसे निकालने में नाकाम रहने के बाद आरोपी उन्हें अयोध्या ले गया और आधार के जरिए खाते से 30 हजार रुपये निकाल लिए। उसने नकदी भी छीनकर बुजुर्ग की पिटाई की और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर्रैया थानाक्षेत्र के भदावल कला निवासी 70 वर्षीय भगवान दत्त जालसाजी और लूट के शिकार हो गए।

मोदी कैबिनेट से डिलिमिटेशन बिल को मंजूरी

नई दिल्ली (आभा)। मोदी कैबिनेट की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में डिलिमिटेशन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत, सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ जाएंगी। इस विधेयक को अब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां पर एनडीए को इसे पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। सरकार ने बीते दिन संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी थीं कि सरकार संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है।

अगर यह बिल दो तिहाई बहुमत के साथ संसद में पास हो जाता है तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 543 से 850 हो जाएगी।



सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं, जोकि बढ़कर 120 हो जाएंगी। वहीं, दक्षिण भारत के राज्य केरल में वर्तमान समय में कुल 20 सीटें हैं, जोकि बढ़कर 30 हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार का दावा है कि उसके पास दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ हो गया है। सबकी नजर डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी पर होगी। पिछली बार इन पार्टियों ने बिल का विरोध किया था, लेकिन कुछ समय से सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि दोनों दल डिलिमिटेशन बिल पर समर्थन दे सकते हैं। इससे एनडीए सरकार को तिहाई बहुमत हासिल कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ इस नए विधेयक को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम न हो। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने पर सहमति जताई है। साल 2051 तक सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

बिल को मोदी कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में लाया गया। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बिल पर चर्चा करने के लिए यह बैठक दोपहर एक बजे सेवा तीर्थ में बुलाई गई थी।

ओमवीर हास्पिटल में आधुनिक लेजर तकनीक से होगा बवासीर का उपचार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ओमवीर हॉस्पिटल में आधुनिक लेजर तकनीक से अब बवासीर का उपचार होगा। यह जानकारी देते हुये हॉस्पिटल की संचालिका डा. अर्चना चौधरी ने बताया कि बवासीर (पाइल्स), भगन्दर (फिस्टुला), फिशर और गुदा संबंधी अन्य जटिल बीमारियों के उपचार के लिए अब मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ओमवीर हॉस्पिटल, कैली अस्पताल गेट नंबर–1 के सामने, बस्ती में आधुनिक लेजर तकनीक के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

डा. अर्चना चौधरी ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आगामी 5 दिसंबर शनिवार को ओमवीर हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर उनकी बीमारी के अनुसार उचित उपचार की सलाह दी जाएगी। शिविर में दिल्ली से वरिष्ठ चिकित्सक डा. इकराम इलाही मरीजों का उपचार करेंगे।

शिविर में बवासीर, भगन्दर,



फिशर, पाइलोनाइडल साइनस, गुदा द्वार पर खुजली तथा पैरों की नसों के फूलने यानी वैरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं की निःशुल्क जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, शिविर में जांच के बाद जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उनके लिए 5 एवं 6 दिसंबर को आधुनिक लेजर तकनीक से उपचार की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों का निर्धारित पात्रता एवं योजना के नियमों के अनुसार लेजर ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। बस्ती में आधुनिक लेजर उपचार की यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इससे बस्ती मंडल ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और पूरे पूर्वांचल के मरीजों को अपने ही क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मोहम्मद अरशद अंसारी बने क्षेत्रीय मंत्री, मोबीन अली को मिली सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी





–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र में संगठनात्मक विस्तार के तहत मोहम्मद अरशद अंसारी को क्षेत्रीय मंत्री तथा मोबीन अली को क्षेत्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बस्ती सहित गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है।

ज्ञात रहे कि मोहम्मद अरशद अंसारी वर्तमान में बस्ती अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, सक्रियता और संगठनात्मक कार्यों को देखते हुए उन्हें गोरखपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मोबीन अली को क्षेत्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर क्षेत्रीय मंत्री मोहम्मद अरशद अंसारी और क्षेत्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक मोबीन अली ने संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे।

दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अनस उस्मानी, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा खुशीद अंसारी, अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेहा खातून तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष इस्माइल फारुकी के प्रति आभार व्यक्त किया।

पदोन्नति के लिये काउंसलिंग आदेश जारी करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अनशन जारी, शिक्षकों में आक्रोश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पदोन्नति के लिये काउंसलिंग का आदेश जारी करने की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिक्षकों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठे शिक्षकों ने साफ कहा कि जब तक पदोन्नति का आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक अनशन किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा। इसी कड़ी में बीएसए को ज्ञापन देकर काउंसलिंग आदेश जारी करने की मांग किया गया।

अनशन के दूसरे दिन अनशन पर बैठे आनंद शुक्ला, किरन देवी, राममोहन उपाध्याय, अखिलेश चौधरी, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी को जिला पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अनशन शुरू कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक–शिक्षिकाएं मौजूद रहे और पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। दो विकलांग शिक्षक भी अनशन पर बैठे।

संघ जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला ने कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जानबूझकर आदेश को लटकाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि काउंसलिंग से पदोन्नति न कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करोड़ों रुपये की वसूली करने की फिराक में हैं। उन्होने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की वसूली नहीं होने दी जाएगी। पदोन्नति सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही होगी। कहा कि ब्लाकों में जो वरिष्ठता सूची काउंसलिंग के नाम पर भेजी गयी थी उस पर नाम के सामने शिक्षकों से सादा हस्ताक्षर करा लिया गया। उसी को जनपद स्तर की काउंसलिंग मानकर पदोन्नित आदेश जारी करने का षड्यंत्र विभागीय स्तर पर किया जा रहा है।

अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला ने कहा कि पहले भी काउंसलिंग कराकर शिक्षकों को पदोन्नति देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को धोखा दिया गया। अब शिक्षक किसी भी आश्वासन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। जब तक लिखित आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक अनशन जारी रहेगा। उन्होने कहा कि सोमवार से अनशन के साथ ही दोपहर बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जायेगा। धरने में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय भी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी देते हुये संघ के जिला प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि बीएसए कार्यालय पर जारी अनशन को अभय सिंह यादव, शुक्ला, शौल शुक्ल, अभिषेक उपाध्याय, प्रदीप कुमार मिश्रा, मोहम्मद याकूब, अरविंद कुमार, कृष्ण बिहारी पांडे, रजनीश मिश्रा, कृष्ण बहादुर पाल, ओमप्रकाश, बृजेश चौधरी, ओमकार उपाध्याय, कन्हैयालाल भारती, हरीश चौधरी, रिता शुक्ला ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पदोन्नति शिक्षकों का हक है, इसे और टाला नहीं जा सकता। काउंसलिंग से पदोन्नति ही एकमात्र पारदर्शी तरीका है। अगर विभाग ने जल्द आदेश जारी नहीं किया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा।



–पदोन्नति के नाम पर शिक्षकों से वसूली बर्दाश्त नहीं– उदयशंकर
–दो विकलांग शिक्षक भी अनशन पर बैठे

पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक पिछले कई वर्षों से पदोन्नति की आस में बैठे हैं। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति उनका अधिकार है, लेकिन विभागीय लापरवाही और टालमटोल के कारण हजारों शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं। अगर समय रहते आदेश जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और जनपद के सभी शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

धरने में मुख्य रूप से चंद्रिका सिंह, अरुण पाण्डेय, रविंद्र कुमार, अभिषेक द्विवेदी, शिव शंकर सिंह, मजहबी खातून, प्रणव मिश्रा, अमित कुमार वर्मा, ओमप्रकाश, कुसुम लता, क्षमा खातून, कुलदीप कुमार त्रिपाठी, कृष्ण बिहारी पाण्डेय, रजनीश मिश्र, प्रदीप कुमार मिश्र, स्कन्द मिश्र, हरीश प्रसाद चौधरी, ओंकार उपाध्याय, जय राम चौधरी, रीता शुक्ला, कन्हैयालाल भारती, मो. याकूब, सालेहा बेगम, अनीता, क्षमा खातून, नसीमा खातून, तरन्नुम नाज, मीनाक्षी पाठक, सुधा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

फिर से जारी होगा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम

इलाहाबाद (आभा)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को पीसीएस–2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (एमआरसी) के तहत अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करने का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।



न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने संजय कुमार और तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक थे, इसके बावजूद उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के तहत अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया।

याचियों ने अदालत से मांग की थी कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक हैं, उन्हें उनकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाए। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को चयन प्रक्रिया नए सिरे से पूरी करने और प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम दोबारा जारी करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपीपीसीएस–2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। अब आयोग को अदालत के निर्देशों के अनुसार परिणाम संशोधित कर नए सिरे से जारी करना होगा।

बहन की शादी के दिन फंदे से लटकता मिला युवक का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र के डिहुकपुरा उर्फ शुकुलपुरा गांव में चचेरी बहन की शादी के दिन 26 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हाल में फंदे से लटकता मिला। घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार की देर रात राज यादव की चचेरी बहन की शादी नगर पंचायत गायघाट स्थित एक मैरिज हॉल में हो रही थी। परिवार और रिश्तेदार शादी समारोह में व्यस्त थे। राज भोजन करने के बाद रात करीब 12 बजे घर लौट आया। देर रात करीब दो बजे परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो राज छप्पर में बांस से मफलर के सहारे लटकता मिला। यह देख घर



में चीख–पुकार मच गई।परिजनों और ग्रामीणों ने आनन–फानन में उसे फंदे से उतारकर बनहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने लालगंज पुलिस को जानकारी दी। चौकी इंचार्ज कुदरहा विवेकानंद तिवारी ने परिजनों से पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज दो भाई–बहनों में दूसरे नंबर पर था। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

विकसित भारत युवा संसद जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में अमरेश दूबे प्रथम, एकता राव को द्वितीय स्थान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को मेरा युवा भारत बस्ती द्वारा 'विकसित भारत युवा संसद 2027 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन श्रीकृष्ण पाण्डेय इण्टर कालेज के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता विकसित करने का यह प्रयास सराहनीय है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अंकुर वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद शुक्ल ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कहा कि नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में युवाओं में जागरूकता से समस्या का हल निकलेगा।

जिला युवा अधिकारी अंशिका सिंह ने बताया कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत विशेष गतिविधि के रूप में करायी गयी प्रतियोगिता में अनेक युवक–युवतियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का विषय 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' निर्धारित था जिस पर प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे।



–विजेता पुरस्कृत, नशे के विरूद्ध एकजुटता का संकल्प

अमरेश दूबे प्रथम, एकता राव द्वितीय और निश्चिय सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले युवाओं को प्रमाण–पत्र और शील्ड देकर उत्साहवर्धन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के विजेताओं को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जायेगा।

श्रीकृष्ण पाण्डेय इण्टर कालेज प्रधानाचार्य योगेश शुक्ल, सुनीता पाण्डेय, डा. परीक्षित सिंह, डा. राजकिशोर वर्मा, सत्यम शुक्ल ने निर्णायक की भूमिका निभायी। कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में ओम प्रकाश मिश्र, अंकित त्रिपाठी, दिलीप गुप्ता, मो. आरिफ, पिंकी चौधरी, अर्जुन उपाध्याय, उमा मिश्र, ऋषभदेव त्रिपाठी, नागेन्द्र कुमार शुक्ल, संध्या यादव, चन्द्रदेव शर्मा, विवेक पाण्डेय, शशिकान्त शुक्ल, आयुषी ओझा आदि ने योगदान दिया।

मण्डलायुक्त से वार्ता के बाद भाकियू का धरना स्थगितः प्रतिनिधि मण्डल ने उठाया किसानों की समस्याओं का मुद्दा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मण्डलायुक्त वैभव श्रीवास्तव से वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने धरना स्थगित कर दिया। स्थानीय मुददों और गन्ना मूल्य 600 रूपया प्रति क्विंटल किये जाने आदि की मांगों को लेकर किसान और मजदूर मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर में पूरी रात डटे रहे, लिटटी, चोखा, खिचडी बना। शुक्रवार की सुबह उप जिलाधिकारी सदर पहुंचे तो किसान इस बात पर डट गये कि वे मण्डलायुक्त से वार्ता के बाद ही धरना स्थगित करेंगे। मण्डलायुक्त वैभव श्रीवास्तव ने भाकियू प्रतिनिधि मण्डल से खाद, बीज, गन्ना मूल्य, धान खरीदारी सहित मण्डल स्तर के समस्याओं पर जिला गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में विन्दुवार वार्ता किया और समस्याओं के समाधान का प्रभावी आश्वासन दिया।

मण्डलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की पहल पर भाकियू प्रतिनिधि मण्डल ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। प्रतिनिधि मण्डल में मण्डल अध्यक्ष जयराम चौधरी, भाकियू के बस्ती जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी, संतकबीरनगर जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी, सिद्धार्थनगर जिलाध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रमेश चौधरी, त्रिवेनी चौधरी, सत्य प्रकाश दूबे आदि शामिल रहे। मण्डलायुक्त से वार्ता के बाद भाकियू पदाधिकारियों ने बताया कि मण्डलायुक्त ने समस्याओं को गंभीरता से लिया और मण्डल स्तर के समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों से वार्ता किया।



धरना स्थल पर दूसरे दिन पूर्वांचल अध्यक्ष अनूप चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष किसान, ब्रम्हादीन, शोभाराम ठाकुर, डा. आर.पी. चौधरी, दीवानचन्द पटेल, कन्हैया चौधरी मुन्नू चौधरी, राम प्रताप, हृदयराम यादव, सूर्य प्रकाश चौधरी, स्वामीनाथ, सन्तोष ओझा, बुद्धिराम, राम सूरत चौधरी, रामसागर, कृष्ण चन्द्र, बगेरू चौहान, घनश्याम मिश्र, विमल कुमार, रामचन्दर सिंह, जगदीश प्रसाद, गंगाराम, परशुराम शर्मा, रामफेर, महाबीर, रामनयन निषाद, रामभजन, कलावती, सीताराम, विजय बहादुर, सुभावती देवी, राधेश्याम, रामचरित्र, राम सुरेमन, राम सागर चौधरी, रामा यादव के साथ ही बस्ती मण्डल के अनेक भाकियू पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 नवम्बर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

परिसीमन और महिला आरक्षण

संसद एक बार फिर उस सवाल पर लौट रही है, जिस पर अप्रैल में सरकार को अपनी पहली बड़ी संसदीय हार झेलनी पड़ी थी। लोकसभा 30 नवंबर और राज्यसभा 2 दिसंबर को बैठेगी और कार्यवाही 3 दिसंबर तक चलेगी। सरकार इसे आवश्यक सरकारी कामकाज बता रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 फिर लाएगी, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। आज 27 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। अप्रैल का घटनाक्रम इस पूरी बहस की कुंजी है। तब सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया था और 17 अप्रैल को यह संशोधन लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 मतों से गिर गया, जो दो–तिहाई बहुमत से काफी कम था। उस दिन सदन में मौजूद 528 सदस्यों के हिसाब से जरूरी आंकड़ा 352 था। अंतिम क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के लिए 50 फीसदी आनुपातिक बढ़ोतरी को बिल में जोड़ने की पेशकश की, पर विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। इसके बाद सरकार ने परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े दोनों साथ वाले विधेयक वापस ले लिए।

इस विवाद की जड़ 2023 के कानून में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी 128वां संशोधन, लोकसभा में 454–2 के भारी बहुमत से पारित हुआ था। राज्यसभा में उसे सभी 214 सदस्यों का समर्थन मिला। पर कानून में पेंच यह था कि आरक्षण जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन पर आधारित है, और मौजूदा जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 है। इसलिए 2029 के आम चुनाव से पहले उस आधार पर परिसीमन पूरा होने की संभावना कम मानी जाती है। सरकार का तर्क था कि अगली जनगणना और परिसीमन में समय लगेगा और महिलाओं की भागीदारी टलेगी, इसलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। यही प्रस्ताव विपक्ष को खटका। विपक्ष की आपत्ति दो बातों पर है। पहली, शशि थरूर ने कहा था कि महिला कोटे को परिसीमन से जोड़ना महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बनाना है। दूसरी, दक्षिणी राज्यों को डर है कि उनका प्रभाव घटेगा और बदलाव का फायदा उत्तर में मजबूत भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस का कहना है कि वह आरक्षण के पक्ष में है, पर परिसीमन और सीटें बढ़ाना अनिवार्य बनाने पर उसे आपत्ति है। पी. चिदंबरम का सुझाव है कि अनुच्छेद 334 हटा दिया जाए तो आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है।

खैर, तमाम किंतु–परंतु के बीच मोदी सरकार के सामने अब असली लड़ाई संख्या बल की है। 540 की प्रभावी सदस्य संख्या में बिल पास कराने के लिए 361 वोट चाहिए, जबकि अप्रैल में एनडीए को 298 मिले थे। एनडीए के पास अभी करीब 320 सांसद हैं और सरकार की नजर डीएमके के 22 और एनसीपी (शरद पवार) के आठ सांसदों पर है। इन दोनों को जोड़ने पर भी आंकड़ा 355 तक पहुंचता है, यानी पांच कम। इसलिए वाईएसआरसीपी, जेएमएम, वीसीके और आरएलपी जैसे छोटे दलों से बातचीत चल रही है और कुछ विपक्षी सांसदों की गैरहाजिरी की भी उम्मीद है। बहरहाल, कयास यह लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार को लोकसभा में 41 और राज्यसभा वोट कम पड़ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में एनडीए के 142 सदस्य हैं और 161 चाहिए, यानी 19 की कमी। आंकड़ों का यह अंतर अलग–अलग गणना का नतीजा हो सकता है, पर दोनों में कमी साफ है।

इस समय डीएमके की शर्तें इस पूरे गणित का केंद्र हैं। पार्टी उसी सूरत में समर्थन की बात कर रही है, जब तमिलनाडु का करीब 7.2 फीसदी हिस्सा सुरक्षित रहे। वह 1971 की जनगणना पर आधारित रोक को 25 साल और बढ़ाने और ऐसे सुरक्षा उपाय बिल के पाठ में ही शामिल करने की मांग भी कर रही है। सुप्रिया सुले ने भी बिल देखकर रुख तय करने की बात कही है और सभी राज्यों में 50 फीसदी की समान बढ़ोतरी पर समर्थन के संकेत दिए हैं। सरकार के लिए असली चुनौती इन गारंटियों को कानूनी शक्ल देना है, क्योंकि अप्रैल में विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ऐसे सुरक्षा उपाय मूल बिल में क्यों नहीं थे।

उधर, सियासी बयानबाजी की धार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती और हार के लिए एक विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल में तो उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, सपा और टीएमसी पर आरोप लगाते हुए इसकी तुलना भ्रूण हत्या से कर दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं और मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि विशेष सत्र को नियमित शीतकालीन सत्र का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। एनसीपी (सपा) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। विपक्ष की एकजुटता पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दल बिल के विवादित प्रावधानों में बदलाव चाहते हैं और सुर अलग–अलग दिख रहे हैं। इसके बावजूद सपा, टीएमसी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के रुख से लगता है कि पुराना स्वरूप दोहराया गया तो नतीजा भी पुराना हो सकता है।

अब सवाल यह है कि पांच राज्यों के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फरवरी–मार्च 2027 में चुनाव होने हैं और पंजाब को छोड़कर चारों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। सीधा असर परिसीमन का नहीं होगा, क्योंकि 2027 की शुरुआत का विधानसभा चुनाव मौजूदा नक्शे पर ही लड़ा जाएगा। असर नैरेटिव का होगा। भाजपा हार को महिला प्रतिनिधित्व पर जनमत संग्रह की तरह पेश कर रही है, ताकि जाति और क्षेत्र से परे महिलाओं का एक वर्ग साध सके। बिल पास हुआ तो वह इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं के बीच भुनाएगी। गिरा तो विपक्ष ने फिर रोका महिला आरक्षण बिल का अभियान और तेज होगा।

इस सबके बीच विपक्ष के लिए जोखिम भी है और मौका भी। उसने 2023 में आरक्षण के पक्ष में वोट दिया था और अब परिसीमन के तरीके पर सवाल उठा रहा है। यह तर्क पंजाब जैसे राज्य में असर कर सकता है, जहां अकाली दल ने सभी राज्यों के लिए समान 50 फीसदी बढ़ोतरी के साथ दोनों बिल पारित करने की मांग की है। पर इन मुद्दों की पेचीदगी आम मतदाता तक पहुंचाना कठिन है, जबकि महिला विरोधी का आरोप सरल संदेश है। इसलिए चुनावी असर का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करेगा कि सरकार संशोधित बिल में डीएमके जैसे दलों की चिंताएं दर्ज करती है या नहीं। आज की तारीख में मतदाताओं पर प्रभाव का कोई ठोस सर्वे नहीं है, इसलिए इसे अनुमान ही मानना चाहिए।

नेपाल से जुड़े विवादित मुद्दे और भारत



—पुष्परंजन—



प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई कूटनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत–नेपाल के बीच विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करने पर अपने समकक्ष को राजी कराया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत इतनी लंबी चली कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए निर्धारित समय निकल गया। अंततः उस वार्ता को रद्द कर दिया गया।

बालेन्द्र शाह की दिल्ली यात्रा कितनी सफल रही, इसका वास्तविक परीक्षण मार्च, 2027 में होने वाले स्थानीय चुनावों में होगा। वर्ष 2022 में स्थापित आरएसपी अपेक्षाकृत नई पार्टी है। 9 मार्च, 2026 को स्वतःस्फूर्त रूप से हुए आम चुनाव में बालेन्द्र–लामिछाने की पार्टी की जीत को महज भावनात्मक उबाल मानिए। लोग अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की कारगुजारियों से पक चुके थे। रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह को नेपाली जनमानस ने जमीन से जुड़ा जुझारू नेतृत्वकर्ता माना था। लेकिन अब जब आम नेपाली उन्हें गोल्फ खेलते देखता है तो ठगा–सा महसूस करता है।

नेपाल में गोल्फ राजाओं का खेल रहा है। इसकी शुरुआत और विकास राणा शासकों तथा शाही परिवार के संरक्षण में हुआ था, जिसके कारण लंबे समय तक इसे राजाओं और कुलीनों का खेल माना जाता रहा। कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी गोल्फ खेलने लगे थे। ओली को अक्टूबर, 2026 में दशहरे की छुट्टियों के दौरान काठमांडू के गोकर्ण फॉरेस्ट रिसॉर्ट में गोल्फ खेलते हुए देखा गया था। पांच महीने बाद ओली जनता के हाथों नप गए।

6 नवंबर, 2026 को रोजा लक्जमबर्ग फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बालेन्द्र सरकार के कामकाज को लेकर युवाओं के बीच कुछ हद तक निराशा और थकान देखी जा रही है। ये युवा अब बालेन्द्र की कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गत 10 अक्तूबर, 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, नेपाली कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टियां अपने खोए हुए मतदाताओं को वापस लाने के लिए संगठनात्मक बदलाव और महाधिवेशन कर रही हैं। मधेशी नेता और वामपंथी भी आपसी मतभेद भुलाकर घर वापसी के वास्ते मशक्कत कर रहे हैं।

दिल्ली में क्या हुआ, इसकी जिज्ञासा नेपाल में उन लोगों को ज्यादा है, जो नेपाल फर्स्ट वाले राष्ट्रवादी मूड में हैं। सोमवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के बीच प्रस्तावित बैठक 30 मिनट तक चलने वाली थी। लेकिन यह बैठक काफी लंबी चली और करीब डेढ़ घंटे तक जारी रही। उस दौरान बाकी अधिकारियों को दूर रखा गया। जाहिर है, राजनयिक यही बताते हैं कि दोनों शासन प्रमुखों ने नेपाल–भारत संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मत भूलिए, नरेंद्र मोदी और बालेन्द्र शाह एक ही वंचित समुदाय से आते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच निजी संबंध प्रगाढ़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई कूटनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत–नेपाल के बीच विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करने पर अपने समकक्ष को राजी कराया। यही दिल्ली बैठक की सबसे बड़ी सफलता है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत इतनी लंबी चली कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए निर्धारित समय निकल गया। अंततः उस वार्ता को रद्द कर दिया गया।

नेपाल में 'लियो–लियो, पायो–पायो' (ले लिया–पा लिया) के नारे मुख्य रूप से रथ यात्राओं, पारंपरिक उत्सवों और सामुदायिक खेलों के दौरान उत्साह तथा सामूहिक शक्ति बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। राजनीति में भी कुछ इसी भाव से सत्ता समर्थक अति उत्साह में 'लियो–लियो, पायो–पायो' करने लगे हैं। लेकिन अभी बहुत से जटिल मुद्दों को सुलझाना बाकी है। काठमांडू–भैरहवा–लखनऊ के बीच जिस दोतरफा हवाई मार्ग पर सहमति बनी है, उस पर भी अभी तकनीकी चर्चा होनी है, खासकर भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ानों की ऊंचाई को लेकर।

दोनों देश नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल के दौरान सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते किन–किन उपायों पर काम करेंगे? अभी सब कुछ अंधेरे में है। जब तक इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, फेसबुकिया तुक्केबाजी जोखिम भरा काम है। गोरखपुर और बागडोगरा दोनों ही रणनीतिक रूप से अहम रक्षा केंद्र हैं, जहां मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के स्टेशन और आसपास भारतीय सेना की सैन्य इकाइयां तथा सुविधाएं मौजूद हैं।

ध्यान रहे कि भैरहवा हवाई अड्डे का निर्माण चीन की एक सरकारी कंपनी (नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप) द्वारा किया गया है। इस हवाई अड्डे का रखरखाव अब भी चीन के जिम्मे है। यह हवाई अड्डा भारत–नेपाल सीमा (उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर) से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी कम दूरी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग अनिवार्य हो जाता है, जो संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों के ऊपर से गुजरता है। नेपाल की आपत्ति के बावजूद लिपुलेख–लिम्पियाधुरा मार्ग से भारत–चीन के बीच 2026 के सीजन में लगभग 1.46 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार हुआ। इसमें भारत से करीब 74.95 लाख रुपये का निर्यात और चीन से लगभग 75.51 लाख रुपये का आयात शामिल है। चीन ने भी नेपाली नेतृत्व को ऐसी आपत्ति से रोका था। बालेन्द्र शाह पर पुराने प्रधानमंत्रियों का दबाव था कि वे दिल्ली यात्रा के दौरान इस विवादित विषय को उठाएं। वर्ष 1950 की संधि की समीक्षा और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लंबित मुद्दों को उठाकर पूर्व यात्रा की किरकिरी होनी थी। मोदी और बालेन्द्र की बंद कमरे में हुई बैठक ने इन मुद्दों को दरकिनार कर सूझबूझ का ही परिचय दिया। यों, बालेन्द्र शाह ने कहा था कि सीमा पर अतिक्रमण एकतरफा नहीं है। नेपाल ने भी अनगिनत भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण या कब्जा किया है। जून, 2026 के अंत में नेपाली संसद में कही गई इस खरी बात से नेपाल में बहुत से नेताओं की भृकुटियां तन गई थीं। कोई पूछे कि बालेन्द्र शाह की दिल्ली यात्रा से नेपाल को क्या–क्या हासिल हुआ? भारत ने करीब 1.6 अरब डॉलर (15,000 करोड़ रुपये) का पैकेज घोषित किया। इसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए 3,500 करोड़ रुपये का अनुदान तथा ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। आठ सहमति–पत्रों के आदान–प्रदान के दौरान 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के लिए साझा विजन अपनाया गया। इनमें ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रेल कनेक्टिविटी, खेल और उपग्रह सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के गूढ़ार्थ को समझिए, 'भारत–नेपाल एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) की रिपोर्ट बीते दिनों की बात हो गई है। वर्तमान संदर्भ में यह 'अप्रासंगिक' है।' फरवरी, 2016 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा के दौरान आठ सदस्यीय ईपीजी (प्रत्येक देश से चार–चार विशेषज्ञ) का गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि, सीमा विवाद (जैसे कालापानी), व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों की समीक्षा कर बदलते समय के अनुसार सुझाव देना था। वर्ष 2018 में रिपोर्ट तैयार तो हो गई, लेकिन उसका खुलासा दोनों में से किसी पक्ष ने नहीं किया। वह विवादों का एक पिटारा जैसी है!

लेखक जियो–पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

समाजवादी पार्टी का प्रण–पत्र और यूपी का बजट

—संजय सक्सेना—



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछ चुकी है और समाजवादी पार्टी (सपा) ने जन–मन का मैनिफेस्टो, सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रण पत्र जारी कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी इस 28 पन्नों के दस्तावेज में समाज के हर वर्ग युवा, महिला, किसान, गरीब और सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। लेकिन, सियासी गलियारों और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में आने पर इन वादों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? और क्या उत्तर प्रदेश का मौजूदा बजट इस भारी–भरकम खर्च को झेल पाएगा, या फिर इसकी कीमत राज्य की बुनियादी विकास योजनाओं को चुकानी पड़ेगी? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र के केंद्र में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ–साथ युवाओं और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को रखा है। पार्टी के प्रमुख वादों पर नजर डालें तो इनमें सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर असर डालने वाली कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। पात्र महिलाओं और बुजुर्गों को सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता (पेंशन) देने का वादा किया गया है। वहीं, अगले पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और स्नातक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसानों के बकाया बिजली बिलों की 100 फीसदी माफी और तत्काल किसान कर्जमाफी का संकल्प लिया गया है। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 रुपये में भोजन की थाली वाली समाजवादी कैंटीन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली और बंद पड़े 26,000 प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने जैसे वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं।

इन वादों को जमीन पर उतारने के लिए कितने धन की जरूरत पड़ेगी, इस पर दो बिल्कुल अलग–अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की घोषणापत्र समिति के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का दावा है कि पार्टी के इन प्रमुख वादों को सालाना लगभग 80,000 करोड़ रुपये के खर्च में पूरा किया जा सकता है। उनके अनुसार, यह राशि उत्तर प्रदेश के करीब 9 लाख करोड़ रुपये के कुल वार्षिक बजट के दसवें हिस्से से भी कम है, जिसे संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जुटाया जा सकता है। दूसरी तरफ, स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषकों की एक रिपोर्ट में किए गए शुरुआती राजकोषीय आकलन एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। इस आकलन के मुताबिक, यदि इन सभी प्रमुख वादों को एक साथ लागू किया जाए, तो राज्य के खजाने पर सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अकेले 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर ही सालाना 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आने का अनुमान है। यदि राज्य की करोड़ों पात्र महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना दिए जाएं, तो केवल इसी एक योजना का बजट 60,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। इसके अलावा, 25 लाख नई सरकारी नौकरियों के सृजन से वेतन और भत्तों का स्थायी खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली दीर्घकाल में राज्य की देनदारियों को विकराल बना सकती है।

किसी भी नई योजना के लिए धन आवंटित करने से पहले राज्य के मौजूदा बजट की संरचना को समझना जरूरी है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल शुद्ध व्यय 8,50,901 करोड़ रुपये (सकल बजट लगभग 9.12 से 9.13 लाख करोड़ रुपये) अनुमानित है। राज्य की शुद्ध प्राप्तियां 7,32,420 करोड़ रुपये हैं, जबकि राजकोषीय घाटा 1,18,481 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। सबसे खास यह है कि राज्य का प्रतिबद्ध व्यय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पुराने कर्जों के ब्याज भुगतान पर ही यूपी सरकार को 3,53,743 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बजट का लगभग आधा हिस्सा पहले से ही बंधा हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की कटौती संभव नहीं है। शेष बचे बजट में से शिक्षा (12.4 फीसदी), कृषि (9 फीसदी), स्वास्थ्य (6 फीसदी) और कानून–व्यवस्था जैसे अनिवार्य क्षेत्रों का संचालन होता है।

अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जब सरकार का राजस्व व्यय (मुफ्त बिजली, भत्ते, पेंशन और नकद सहायता) अचानक बढ़ता है, तो उसका सीधा असर पूंजीगत व्यय पर पड़ता है। पूंजीगत व्यय वह धन होता है जो एक्सप्रेस–वे, सड़कों, पुलों, नए अस्पतालों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। यही खर्च राज्य में दीर्घकालिक रोजगार पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को गति देता है। वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे और पूंजीगत कार्यों के लिए कुल बजट का लगभग 19.5 प्रतिशत (करीब 1.78 से 2 लाख करोड़ रुपये) आवंटित किया है। यदि सपा सरकार बनने पर घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है, तो यह राशि राज्य के कुल बजट के 17 से 27 प्रतिशत के बराबर होगी। चूंकि एफआरबीएम कानून के तहत राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकती, इसलिए नई सरकार के पास धन जुटाने के केवल दो ही रास्ते बचेंगे या तो वह टैक्स बढ़ाए या फिर बुनियादी ढांचे (पूंजीगत व्यय) के बजट में भारी कटौती करे। चुनावी माहौल में टैक्स बढ़ाना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है, ऐसे में सबसे आसान निशाना विकास परियोजनाएं ही बनती हैं। एक्सप्रेस–वे, मेट्रो विस्तार, नई सिंचाई परियोजनाओं और औद्योगिक पार्कों के लिए आवंटित धन को लोकलुभावन योजनाओं की तरफ मोड़ना पड़ सकता है। लब्बोलुआब यह है कि समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र सामाजिक न्याय और तात्कालिक आर्थिक राहत के नज़रिए से मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हालांकि, राजकोषीय अनुशासन के तराजू पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आता है। यदि पार्टी के 80,000 करोड़ रुपये के अनुमान को भी मान लिया जाए, तब भी यूपी के पहले से तंग बजट में इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। सत्ता में आने पर नई सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह मुफ्त योजनाओं और नकद सहायता के वादों को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश की विकास रफ्तार और पूंजीगत निवेश को पटरी से उतरने से कैसे बचाती है।

पंजाब में भाजपा–अकाली गठबंधन



—ललित गर्ग—

पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का छह वर्ष बाद फिर साथ आना केवल दो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वापसी नहीं है, बल्कि यह पंजाब के बदलते राजनीतिक समीकरणों की महत्वपूर्ण आहट है, इससे आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ेगा और पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषित यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकता है। दोनों दलों का पुराना राजनीतिक रिश्ता, साझा शासन का अनुभव और एक–दूसरे के पूरक सामाजिक आधार इस गठबंधन को विशेष महत्व देते हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होती, लेकिन इतना निश्चित है कि पंजाब में अब मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक, प्रतिस्पर्धी और त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा और अकाली दल का संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के औपचारिक गठन से भी पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के दौर में दोनों दलों ने जिस राजनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी, वह लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में सफल मॉडल बनी रही। अकाली दल का ग्रामीण और सिख समाज में प्रभाव तथा भाजपा का शहरी हिंदू, व्यापारी और मध्यवर्गीय आधार एक–दूसरे के पूरक रहे। इसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के कारण दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में कई बार सत्ता हासिल की। लेकिन 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच यह रिश्ता टूट गया। अकाली दल ने भाजपा से दूरी बनाई और हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस समय यह निर्णय किसानों की भावनाओं और पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में लिया गया था, लेकिन बाद के चुनावों ने यह भी दिखाया कि इस अलगाव की राजनीतिक कीमत दोनों दलों को चुकानी पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता पर शानदार ढंग से कब्जा किया। दूसरी ओर अकाली दल तीन और भाजपा केवल दो सीटों तक सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग–अलग मैदान में उतरे। कांग्रेस ने सात, आम आदमी पार्टी ने तीन और अकाली दल ने एक सीट जीती, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत करीब 18.6 प्रतिशत रहा और अकाली दल को भी लगभग 13.5 प्रतिशत वोट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों दलों के पास अलग–अलग पर्याप्त राजनीतिक आधार है, लेकिन अलग–अलग लड़ने पर वह वोट प्रभावी सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब छह वर्ष बाद दोनों दलों ने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए फिर साथ आने का फैसला किया है। इसे राजनीतिक भूल–सुधार भी कहा जा सकता है और बदली परिस्थितियों की व्यावहारिक स्वीकृति भी। इस गठबंधन का सबसे बड़ा प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ना स्वाभाविक है। 2022 में आप को सबसे बड़ा लाभ विपक्ष के बिखरे होने से मिला था। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा अलग–अलग चुनाव लड़ रहे थे और सत्ता विरोधी मत एकजुट विकल्प में परिवर्तित नहीं हो पाए। अब भाजपा और अकाली दल के साथ आने से यह समीकरण बदल गया है। भाजपा का शहरी और मध्यवर्गीय आधार तथा अकाली दल का ग्रामीण संगठन और पारंपरिक जनसंपर्क यदि प्रभावी ढंग से एक–दूसरे के पक्ष में वोट ट्रांसफर कर पाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ेगी।

युवाओं को माफिया और नकल की पहचान देने वालों से हिसाब मांगना चाहिए –मुख्यमंत्री

संवाददाता–गोण्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के 46,800 छात्र–छात्राओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेरीलाल के सपने दिखाने से विकास नहीं होता। विकास के लिए समय, समर्पण और स्पष्ट विजन चाहिए। पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को माफिया और उपद्रव प्रदेश बनाकर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज वही उत्तर प्रदेश माफिया, कर्फ्यू और दंगा मुक्त होकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। जिनकी सोच केवल परिवार तक सीमित थी, उन्होंने सैफई तक सोचा, जबकि हमारी सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उसकी तकदीर बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टैबलेट केवल एक डिजिटल डिवाइस नहीं, बल्कि युवाओं के लिए चलता–फिरता विश्वविद्यालय है। इसके माध्यम से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस तकनीक का उपयोग अपने भविष्य को संवारने में करें। रील देखने में 30 सेकंड लगाएं, लेकिन अपने कौशल को निखारने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जरूर दें। टैबलेट के साथ सपनों और संकल्पों को भी हमेशा चार्ज रखिए। सपने बड़े होने चाहिए, उसके अनुरूप परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप चार्ज रहेंगे तभी असुरीय शक्तियों और नेगेटिव फोर्सेज डिस्चार्ज होंगी। जब नेगेटिव फोर्सेज डिस्चार्ज होंगी तो आपका भविष्य सुपरचार्ज होगा।

मुख्यमंत्री ने गोंडा और देवीपाटन मंडल के पुराने हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 से पहले गोंडा का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में आया था। देवीपाटन शक्तिपीठ तक पहुंचने वाली सड़कें बेहद खराब थीं। बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिले विकास की दौड़ में इतने पीछे थे कि नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में एक ही मंडल के तीन जनपद शामिल थे। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भी ये जिले प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते थे। लेकिन, आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन चुका है।



बहराइच में मेडिकल कॉलेज संचालित है। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है। आरू संग्रहालय और बेहतर सड़कें इस क्षेत्र के विकास की नई पहचान हैं। पिछले साढ़े नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार ने अकेले देवीपाटन मंडल के लिए 36 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। श्रावस्ती में एयरपोर्ट तैयार हो चुका है और शीघ्र ही हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। अब गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती देश के स्वच्छता सर्वेक्षणों में गंदे शहरों की पहचान से बाहर निकलकर अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत के साथ विकास की नई आभा बिखेर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लखनऊ में 1,594 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करके यहां आए हैं। पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की चार और बहुजन समाज पार्टी की तीन सरकारों के कुल सात कार्यकालों में जितनी नियुक्तियां हुईं, उसके दोगुने से अधिक नियुक्ति पत्र अकेले भाजपा सरकार ने वितरित किए हैं। नियुक्ति पत्र युवाओं के परिश्रम का सम्मान है और उसी तरह आज वितरित किए जा रहे टैबलेट उनके टैलेंट को मंच उपलब्ध कराने का माध्यम हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा साथी ऐप के माध्यम से टैबलेट में 18 हजार से अधिक शैक्षिक कंटेंट और निशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। छात्र–छात्राएं एक विलक पर छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह डिवाइस युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ डिजिटल उद्यमी बनने में भी मदद करेगा।

आईआईएम लखनऊ की स्टडी में सामने आया कि इन उपकरणों के माध्यम से तीन करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम होने में मदद मिली। लेकिन, ध्यान रखें कि एआई आपको सशक्त बनाने वाला उपकरण होना चाहिए, न कि दिमाग पर हावी होने का माध्यम। हर वायरल कंटेंट सही नहीं होता, इसलिए किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले फैक्ट चेक करें और डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखें। इस टैबलेट से फीड नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करिए।

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जर्जर थी। स्कूलों में भवन और शिक्षकों का अभाव था तथा नकल, भूमि, खनन, शराब और वन माफिया पूरे सिस्टम पर हावी थे। पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी– वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है। अब यूपी में रुनो कर्फ्यू, नो दंगा–यूपी में सब चंगाश की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूलों और इंटर कॉलेजों के जर्जर भवनों को नए स्वरूप में विकसित किया गया है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर, खेल मैदान और बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने का मंच मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में मुश्किल से 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो चुकी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाया है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी युवा और बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी नेताओं से सवाल किया कि जब वे सत्ता में थे, तब युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रदेश के विकास के लिए क्या किया? आज घोषणाएं करने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहचान का संकट पैदा करने वाले लोग फिर युवाओं के पास प्रमाणपत्र लेकर पहुंचने का प्रयास करेंगे। राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने वाले लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोएडा जाने से बचते थे। नोएडा को लूट–खसोट का माध्यम बना दिया गया था। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण निवेश के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। पिछली सरकारों की सोच कड़ा और बम तक सीमित थी। हमने अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया और आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। यहां दसवीं, बारहवीं, स्नातक और परास्नातक युवाओं की योग्यता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो युवा जापान और जर्मनी जाना चाहेंगे, उन्हें सरकार अपने खर्च पर संबंधित भाषाओं का प्रशिक्षण दिलाकर विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

उन्होंने बाराबंकी–बहराइच चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के लिए भारत सरकार द्वारा सात हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति, गोंडा–लखनऊ मार्ग के चौड़ाकरण, जरवल रोड के पास घाघरा नदी पर चार लेन पुल, अयोध्या–बलरामपुर–श्रावस्ती कॉरिडोर और गोरखपुर–शामली–पानीपत इकोनॉमिक कॉरिडोर, रुपईडीहा में लैंड पोर्ट और औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास के साथ कतर्नियाघाट और चित्तौरा झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल होना चाहिए। मतदान अधिकार के साथ नैतिक कर्तव्य भी है। युवा साथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। उस समय आज के युवा ही देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। जब युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक शक्तियां कमजोर होंगी और 2047 का उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर एवं विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होगा।

इस अवसर पर गोंडा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह, सांसद बहराइच आनंद कुमार गोंड, पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी, कटरा के विधायक बावन सिंह, तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री, महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे, विधायक बहराइच अनुपमा जायसवाल, विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी, विधायक गौरा प्रभात कुमार वर्मा, विधायक गोंडा सदर प्रतीक भूषण सिंह, विधायक बलरामपुर पलटूराम, विधायक करनैलगंज अजय कुमार, विधायक बलहा सरोज सोनकर, विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, विधायक श्रावस्ती राम फेरन पांडे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह मंजू, प्रज्ञा त्रिपाठी, पदमसेन चौधरी समेत भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से आए मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर टैबलेट प्रदान किए। इस दौरान गोंडा की कुमारी प्रियंका चतुर्वेदी, सुरभि तिवारी, पिंकी सोनी, अर्चिता व सैयद अनस, महाराजगंज की कुमारी मानवी पांडेय, बहराइच की कुमारी अमिता जायसवाल, कुमारी सना बेगम, कुंज बिहारी व शिवेंद्र प्रताप सिंह, श्रावस्ती की कुमारी रिंकिमा वैश्य, साधना मिश्रा, जैनब, भूपेंद्र विश्वकर्मा व राजवीर सिंह, बलरामपुर की कुमारी अर्चना शुक्ला, रमन द्विवेदी, कुमारी सौम्या पांडेय, अभिजीत भट्ट व मोहम्मद सुलेमान सिद्दीकी को मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट प्राप्त हुए।

किसी जाति में माफिया नहीं, जहां हैं वहां कोई कहना नहीं चाहता, अखिलेश को बृजभूषण का जवाब



संवाददाता–बहराइच। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माफिया के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई संबंधी बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है। प्रदेश अपराध मुक्त है। किसी जाति में माफिया नहीं है। जहां माफिया हैं भी, वहां उन्हें कोई माफिया कहना नहीं चाहता। दरअसल सपा अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली और बृजभूषण शरण सिंह समेत कुल 19 लोगों की सूची का जिक्र किया, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड और शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा हाईकोर्ट ने मांगा था। साथ ही कहा कि कोई इन माफिया की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ता।

बृजभूषण ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया और छात्र नेताओं का दमन किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक दल अपने–अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं। कोई एजेंडा जारी कर रहा है तो कोई रैली कर रहा है। चुनाव तक यह सब चलता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के सवाल पर बृजभूषण ने कहा कि वह उनकी माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने गए थे। यह हमारी परंपरा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि योगी मुख्यमंत्री हैं और वह खुद भी राजनीति से जुड़े हैं, उनका बेटा सांसद और विधायक है, ऐसे में चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। मंडल में कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी नहीं हैं। दरअसल शुक्रवार को बहराइच स्थित इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात कही। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। और कहा कि ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके।

दुष्कर्म के बाद जिंदगी की जंग हार गई 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला, आरोपी गिरफ्तार



संवाददाता–महराजगंज। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान रिश्तेदार के कथित दुष्कर्म और मारपीट की शिकार हुई 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहीं, पुलिस ने आरोपी गिरजेश को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

घटना 25 नवंबर को गांव में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। जानकारी के मुताबिक, गांव के एक युवक की बरात दूसरे गांव गई थी। घर के सभी पुरुष बरात में शामिल होने गए थे। इस दौरान रिश्तेदारी में आया दूल्हे की मां के देवर का साढ़ू गिरजेश घर पर ही था। आरोप है कि बृहस्पतिवार की रात करीब नौ बजे वह शराब के नशे में बुजुर्ग महिला के कमरे में घुस गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट भी की। कुछ देर बाद खाना खाने के लिए महिला के बाहर नहीं आने पर उनकी बड़ी बेटी कमरे में पहुंची। वहां उसने गिरजेश को आपत्तिजनक हालत में देखा। इसके बाद वह परिवार की चार–पांच अन्य महिलाओं को लेकर कमरे में पहुंची। महिलाओं को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर बरात में गए परिजन घर लौटे और आरोपी की तलाश शुरू की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बृहस्पतिवार को पुलिस टीम ने पड़री उर्फ मीरगंज के टोला मुंडेरी के पास से गिरजेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अनूप तिवारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उधर, पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर बृहस्पतिवार को उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसपी महराजगंज शशि मोहन अवस्थी ने बताया कि महिला की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया गया है। मामले में आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के काफिले की तीन गाड़ियां आपस में टकराईं, सभी क्षतिग्रस्त



–कुशीनगर। हाटा–कप्तानगंज मार्ग पर मथौली नगर पंचायत कार्यालय के सामने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के काफिले में शामिल तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में पुलिस की स्कॉर्ट समेत तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुकरौली ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान और पुलिसकर्मी बाल–बाल बच गए।

हाटा–कप्तानगंज मार्ग पर मथौली नगर पंचायत कार्यालय के सामने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के काफिले में शामिल पुलिस की स्कार्ट समेत तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में सुकरौली की ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान और पुलिसकर्मी बाल–बाल बच गए। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का काफिला शुक्रवार को कप्तानगंज की ओर से हाटा जा रहा था। मथौली नगर पंचायत कार्यालय के सामने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला हाटा की ओर रवाना हो गया। इसी दौरान काफिले के पीछे चल रही तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें गोरखपुर के किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी की गाड़ी, सुकरौली ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो और सुरक्षा में चल रही टाटा सूमो शामिल थीं।

टक्कर की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद काफिले में कुछ देर के लिए अफरा–तफरी मच गई। काफिले में शामिल लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कराया। इसके बाद काफिला आगे के लिए रवाना हो गया।

ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की, कलेक्ट्रेट तक निकाला जुलूस, 3 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी

संवाददाता–देवरिया। ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जिला संयोजक अरुण कुमार मिश्र के नेतृत्व में मनरेगा कर्मचारी सुभाष चौक से निकले और शहर के सिविल लाइन रोड से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मानदेय बढ़ाने समेत विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई। मांगें पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले 20 साल से ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं।



मनरेगा और अब वीबी–जी राम जी के तहत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिलाने में उनकी भूमिका है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मानदेय कम से कम 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, इसके लिए अलग बजट रखने और नियमित भुगतान की मांग की गई। कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के सभी काम कनेक जॉब चार्ट में शामिल करने और पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की मांग की गई। संगठन ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 23 नवंबर से विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान काम का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया था। 19 नवंबर को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को भेजे पत्र में मानदेय बढ़ाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ भुगतान समेत अन्य मांगें रखी गई थीं।

संगठन के मुताबिक, अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे।

दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल



संवाददाता–बहराइच। गिलौला थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी शाहिद अली शुक्रवार रात पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में घायल हो गया। 23 नवंबर को गिलौला क्षेत्र के एक गांव में बालिका से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही थीं।

शुक्रवार रात गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिसवारा–गिलौला बाइपास तिराहे पर मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, आरोपी भागने लगा और टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया।

गिरफ्तार आरोपी शाहिद अली, हबीब अली का बेटा और सिसवा, थाना भिनगा का निवासी है। उसके पास से अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की टीवीएस फीनिक्स मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस के मुताबिक, बाइक भिनगा कोतवाली में दर्ज चोरी के मुकदमे से जुड़ी है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की गयी।

एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठी महिला, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप

संवाददाता–महराजगंज। दुष्कर्म के एक मामले में अदालत से गैर जमानती वारंट (छठें) जारी होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज महिला शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठ गई। महिला ने कोतवाली पुलिस के अधिकारियों पर आरोपी को बचाने और जानब



उसका कहना था कि वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराने के बाद से वह न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उसे केवल आश्वासन मिल रहा है। करीब ढाई बजे सदर सीओ अंकुर गौतम महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिला ने धरना समाप्त कर दिया।

महिला ने सदर में तैनात उपनिबंधक और शैलेंद्र सिंह चौहान के विरुद्ध वर्ष 2023 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश पर एससी–एसटी कोर्ट ने आरोपी शैलेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बावजूद पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

महिला का आरोप है कि आरोपी मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और वर्तमान में गोरखपुर में इंपीरियल फ्रेश बिल्डिंग के पास रह रहा है। आरोपी के ठिकाने की जानकारी होने और अदालत से वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शुक्रवार को महिला शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई। शुरुआत में पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी रही। महिला का कहना था कि उसने इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ से भी मुलाकात की थी, लेकिन वहां से भी केवल आश्वासन मिला। वहीं, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से मिलने के लिए करीब तीन घंटे इंतजार करने के बावजूद उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। महिला ने चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने को मजबूर होगी। करीब ढाई बजे सदर सीओ अंकुर गौतम महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को समझाया और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद महिला ने धरना समाप्त कर दिया।

चालक को डीसीएम ने रौंदा, मौत

संवाददाता–बहराइच। रिसिया थाने के जगदीशपुर सोखा गांव में स्कूल के पास शुक्रवार सुबह एक जुगाड़ वाहन का पहिया गड्ढे में जाने से पलट गया। सड़क पर गिरे घायल चालक को पीछे से आ रही डीसीएम रौंदते हुए निकल गई। जिसके चलते चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।रिसिया थाने के जगदीशपुर सोखा गांव में ग्लोबल आफ लर्निंग स्कूल के पास शुक्रवार सुबह लगभग नौ बजे एक बाइक जोड़ बनाए गए जुगाड़ वाहन को एक पहिया गड्ढे में चले जाने से पलट गया।

जिसके चलते चालक दरगाह थाने के नूरबीदन तक मोहल्ले निवासी कलाम (28) पुत्र अनवर सड़क पर गिरा ही था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम उसे रौंदते हुए निकल गई। जिसके चलते कलाम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान होने पर मृतक के परिजनों को जानकारी दी।

शादी समारोह में किशोर की चाकू मारकर हत्या



संवाददाता–गोण्डा। गुरुवार रात करीब 11:15 बजे बाराती डीजे और रोड लाइट के साथ नाचते–गाते हुए लड़की पक्ष के घर द्वार पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि बाराती पक्ष के एक अज्ञात व्यक्ति ने किशोर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी आंत तक बाहर आ गई।

चाचा ताहिर ने बताया कि 26 नवंबर को अहिरौली जोकहा निवासी रामकेवल शर्मा की बेटी मनीषा की शादी थी। रात को बाराती डीजे और रोड लाइट के साथ नाचते–गाते हुए द्वार पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला मोहम्मद हामिद (16) पिता झिनकन भी बारातियों के साथ नाच रहा था। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हामिद पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर कई घाव के निशान हो गए। घटना के बाद गांव के शुभम मिश्रा और रमजान उसे बाइक से इलाज के लिए सीएचसी बभनजोत ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। हामिद के पिता झिनकन गांव में मजदूरी करते हैं। चार भाइयों में हामिद सबसे छोटा था। उसकी एक बहन भी है, जिसकी शादी गांव वालों ने चंदा जुटाकर 2026 में कराई थी।

पिता झिनकन ने बताया कि गांव में एक बेटी की शादी थी, जिसके दरवाजे पर बारती नाच–गाना कर रहे थे। इसी दौरान उनके भाई ने आकर सूचना दी कि किसी ने उनके बेटे को चाकू मार दिया है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो देखा कि बेटा सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा था।

उन्होंने बताया कि उनकी और उनके बेटे की गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है। पिता ने कहा– आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। पुलिस जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे।

औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, 10 गांवों के किसान बोले– खेत नहीं देंगे



संवाददाता–सिद्धार्थनगर। जिस जमीन पर कई पीढ़ियों से खेती कर परिवार का पेट पाल रहे हैं, जहां साल में दो–दो फसलें पैदा होती हैं, अब उसी जमीन के छिनने का डर किसानों को कलेक्ट्रेट तक खींच लाया। बांसी तहसील के छितौनी न्याय पंचायत क्षेत्र के 10 गांवों की कृषि भूमि यूपीसीडा के औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत किए जाने की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना खेतों का सर्वे कराया गया। गांव में लेखपालों के ट्यूबवेल और बोरिंग आदि की जांच करने पहुंचने पर उन्हें जमीन के औद्योगिक परियोजना में जाने की जानकारी हुई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन बेहद उपजाऊ और बहुफसली है। कई परिवारों के पास खेती के लिए यही एकमात्र जमीन है। यदि इसका अधिग्रहण हुआ तो उनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं बचेगा। वे कई पीढ़ियों से इसी जमीन पर निर्भर हैं। ऐसे में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए उनकी कृषि भूमि लेना उन्हें मंजूर नहीं है। किसानों ने मांग की कि फैक्टरी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन कहीं दूसरी जगह तलाश की जाए। मनिकौरा नानकार ग्राम पंचायत के छितौनी गांव निवासी किसान केवल बहन चौधरी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि छितौनी न्याय पंचायत के करीब 10 गांवों की जमीन यूपीसीडा की फैक्टरी और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए ली जानी है। लेकिन अब तक गांव के लोगों को इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। लेखपाल जब गांव में ट्यूबवेल, बोरिंग आदि की जांच करने पहुंचे, तब किसानों को जमीन के सर्वे और अधिग्रहण की आशंका की जानकारी हुई। इससे ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश है। शुक्रवार को दिशा की बैठक चल रही थी। इसी दौरान प्रभावित गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और जिलाधिकारी से मिलने की मांग की। उनका कहना था कि इतने बड़े फैसले से पहले प्रभावित किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना–पत्र देकर उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने और औद्योगिक परियोजना के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने की मांग की।किसानों का साफ कहना है कि वे औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए उनकी पीढ़ियों की आजीविका का आधार बनी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। बंजर, परती और अनुपयोगी सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। किसानों का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

प्रदीप कुमार पाण्डेय ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से मांगों को लेकर धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दूसरे वर्गों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा रही है, जबकि ग्राम रोजगार सेवकों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपए प्रतिमाह करने और इसके भुगतान के लिए अलग बजट रखने की मांग की। ज्ञापन में रोजगार सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज देने, ग्राम रोजगार सेवकों के लिए एचआर पॉलिसी लागू करने और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के सभी काम जॉब चार्ट में शामिल करने की मांग भी की गई। पदनाम बदलकर 'ग्राम विकास सहायक' करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

रोजगार सेवकों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं होने पर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के समस्त ग्राम रोजगार सेवक 3 दिसंबर 2026 को विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।

ग्राम रोजगार सेवकों ने 24 हजार मानदेय मांगा, कैशलेस इलाज और 'ग्राम विकास सहायक' पदनाम की मांग



संवाददाता–संतकबीरनगर। ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय बढ़ाने और सुविधाएं देने की मांग की। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सैकड़ों रोजगार सेवक विकास भवन में जुटे। दोपहर 3 बजे वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। रोजगार सेवकों ने कहा कि वे करीब 20 साल से ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने में उनकी भूमिका रहती है। उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

खेल संगम के दूसरे दिन खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–



बस्ती। राष्ट्रीय युवा संघ (एनएवाई) के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय बस्ती खेल संगम 2026 के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम सहित विभिन्न खेल स्थलों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश, उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतिभाग किया।

आयोजन के दूसरे दिन वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन एवं फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा का जज्बा देखते ही बन रहा था। विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने एक–दूसरे को कड़ी चुनौती देते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सतीश सोनकर, राजेश पाल चौधरी, ट्रैफिक प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी, भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र चौधरी, छात्र नेता सचिन सिंह, समाजसेवी राजीव जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार पुनीत ओझा एवं वरिष्ठ समाजसेवी रामानुजेंद्र पांडेय सहित अनेक गणमान्य लोगों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया।

अतिथियों ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। दूसरे दिन की प्रतियोगिताओं में विद्यालयों की सक्रिय सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खेल विभागालय एवं जनता इंटर कॉलेज के बीच मुकाबला हुआ। वहीं कबड्डी में उर्मिला एजुकेशन एकेडमी एवं रामबाग विद्यालय की टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फुटबॉल प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज एवं किसान इंटर कॉलेज की टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिला।

बैडमिंटन प्रतियोगिता में बेगम खैर एवं एनआईएस स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त आरसीसी स्कूल, ओमनी स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के बच्चों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आयोजकों ने बताया कि बस्ती खेल संगम की सभी खेल प्रतियोगिताओं में विजेता एवं उपविजेता टीमों को 29 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले 15वें बस्ती मैराथन कार्यक्रम के अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर सभी विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं सम्मान प्रदान कर उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

रोजगार मेले में 763 युवाओं ने कराया पंजीकरण

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुक्रवार को त्रिलोकनाथ पीजी कॉलेज में विधानसभा स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से आयोजित मेले में 17 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें 763 युवक–युवतियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 412 मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। रोजगार मेले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम हैं। उन्होंने युवाओं से ऐसे आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने कहा कि विभाग युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिलना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। मेले में युवाओं ने बायोडाटा के साथ साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अरुण शाही ने किया। आयोजन में राजकीय आईटीआई जहांगीरगंज के प्रधानाचार्य विनोद सिंह, राजकीय आईटीआई आलापुर के अनुदेशक चंद्रदीप शर्मा और जिला सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों ने सहयोग किया।

बैंकाक से चांदी की परत चढ़ाकर लाया जा रहा था करोड़ों का सोना, गोरखपुर में तस्करी नेटवर्क का खुलासा

संवाददाता–गोरखपुर। बैंकाक से सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य सीमा शुल्क की जांच से बचने के लिए सोने के गहनों पर चांदी की परत चढ़वाकर भारत लाते थे। गहने पहनकर आने के कारण उन पर सामान्य तौर पर संदेह नहीं होता था। कड़े और चेन जैसे सोने के गहनों पर चांदी की कोटिंग कराकर उन्हें चांदी का बताने की कोशिश की जाती थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बांसगांव क्षेत्र के मऊखुर्द निवासी दीपक तिवारी और उसका भाई मुकेश तिवारी बैंकाक में रहकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। इनके लिए गोरखपुर में कई लोग काम करते थे। अब इस मामले में घंटाघर के एक सर्राफ की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीमा शुल्क विभाग की राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) भी तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दीपक और मुकेश अपने माता–पिता के साथ बैंकाक में रहते हैं। गोरखपुर में उनके लिए आशुतोष शुक्ला काम करता था। सुनील मिश्रा दीपक का साला है और वह भी इसी नेटवर्क से जुड़ा था। अजय यादव भी दीपक के लिए काम करता था। चंदन तिवारी जेल भेजे गए आशुतोष का साला है। कृष्णकांत मुख्य आरोपित दीपक का भतीजा और आयुष उर्फ निखिल व प्रियांशु उसके भांजे बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी अलग–अलग भूमिका में सोने को बैंकाक से भारत लाने और उसकी बिक्री कराने के काम में जुड़े थे। पूछताछ में तस्करी के इस तरीके की जानकारी सामने आई है। आरोपितों के मुताबिक, सोना और चांदी को लेकर सीमा शुल्क के नियमों में अंतर का फायदा उठाने के लिए यह तरीका अपनाया जाता था। सोने के गहने बनवाकर उन्हें पहन लेते थे और फिर उन पर चांदी की कोटिंग करा देते थे। इससे गहने चांदी के नजर आते थे। कड़ा भी सोने का था, लेकिन उस पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी।



आरोपितों ने बताया कि सोना 20 ग्राम तक लाने की छूट है, जबकि इससे अधिक लाने पर 15 प्रतिशत कर देना पड़ता है। चांदी की सीमा अधिक होने के कारण वे सोने को चांदी बताकर लाते हैं। इन दावों और तस्करी के तरीके की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। कैंट थाना पुलिस की टीम कृष्णकांत व चंदन तिवारी की तलाश में छापेमारी कर रही है। उनके पकड़े जाने पर ही शेष सोना बरामद होने की उम्मीद है। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि नामजद आरोपितों की तलाश चल रही है। उनके पकड़े जाने पर नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। पुलिस के मुताबिक, 22 नवंबर को आशुतोष बैंकाक से कोलकाता होते हुए गोरखपुर पहुंचा था। उसके साथ सोने के गहने थे। यहां घंटाघर में उनकी बिक्री की तैयारी थी। इसी मामले में छात्रसंघ चौराहे पर लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने आशुतोष शुक्ला और सुनील मिश्रा को गिरफ्तार कर करीब 960 ग्राम सोना और दो लाख रुपये नकद बरामद किए थे। बरामद सोने की कीमत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई थी। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बैंकाक से सोना लाने, गोरखपुर में उसे खपाने और भुगतान करने की पूरी व्यवस्था कैसे संचालित होती थी।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनकिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
क0 वाद सं0–T202617140305662
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर महोदय बस्ती जिला बस्ती
श्रीमती नीतू आदि
बनाम
रामबेलास आदि
1. रामबेलास पुत्र सिवधन 2. सुभागी देवी पत्नी रामबेलास 3. सुभागी इन्द्रवती नावालिग पुत्री कृष्णानन्द 4. मायावती पुत्री कृष्णानन्द साकिनान खोरिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 14–12–2026
वाजेह हो कि नापके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाफिक किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 27 माह 11 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–273/2026
पारसनाथ (मृतक) आदि
बनाम
अशोक आदि
1. अशोक पुत्र स्वामीनाथ 4. नरसिंह पुत्र विजयेश्वर 6. जन्मेजय पुत्र रामेन्द्र 7. सन्ध्या 8. संजू पुत्रीगण जन्मेजय 10. रेखा देवी पत्नी कृष्ण चन्द्र 11. अमर 12. अरविन्द 13. अजीत पुत्रगण कृष्ण चन्द्र 14. सीमा पुत्री कृष्ण चन्द्र 15. पवन कुमार पुत्र स्वामीनाथ निवासीगण मौजा करही तप्प कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–12–2026
हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 16 माह 12 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाफिक हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद ऊमूर तनखीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
अदालत–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–178/2024
सुबाष आदि
बनाम
रिवई आदि
1–रिवई पुत्र जोखू 2. बबलू 3. दिनेश 4. दुर्गेश पुत्रगण रिवई 5. मैना पत्नी बबलू 6. पुष्पा पत्नी दिनेश 7. इन्द्रा पत्नी रिवई साकिनान मौजा चितरगड़िया तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 10–12–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 10 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाफिक किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

बिना सुनवाई पत्रावलियों के निस्तारण का आरोप, वकीलों ने एसडीएम न्यायिक के न्यायालय पर किया हंगामा



संवाददाता–अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील में शुक्रवार को एसडीएम न्यायिक के न्यायालय में बिना सुनवाई पत्रावलियों के निस्तारण का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि एसडीएम न्यायिक प्रवीण कुमार द्वारा बिना सुनवाई किए मनमाने तरीके से पत्रावलियों का निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार उनसे वार्ता कर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बार–बार शिकायत के बावजूद न्यायालय के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। इससे नाराज होकर उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ता बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। इस मौके पर बार एसोसिएशन मंत्री बृजेश कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष अंसार अहमद खान, संदीप कुमार शुक्ला, प्रहलाद तिवारी, जितेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार पांडेय समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–434/2016
अम्बिका सिंह
बनाम
अभयराज सिंह
4/1 रणजीत सिंह 4/2 बलवीर सिंह 4/3 रणधीर सिंह 4/4 राणा प्रताप सिंह 4/5 कुवंर सिंह पुत्रगण स्व0 रामचरित्र सिंह समस्त निवासीगण ग्राम भरौली बाबू तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 29–01–2027
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुदाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस हैं और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 29 माह 01 सन 2027 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

सड़क हादसे मे युवक की मौत

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। मालीपुर के सैदपुर भितरी के पास शुक्रवार सुबह एनएच की तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गौरव तिवारी 18 की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक दिवाकर और वैभव गंभीर रूप से घायल हो गए।

अदालती नोटिस

सन् 1890 के अधिनियम 8 की धारा 11 के अधीन सूचना
न्यायालय– श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, सिद्धार्थनगर जिला–सिद्धार्थनगर
प्रकीर्णवाद सं0– 119/2026
श्वेता सिंह
बनाम
सरकार उत्तर प्रदेश
1– सरकार उत्तर प्रदेश 2– अखिलेश सिंह उम्र लगभग 38 साल पुत्र जितेन्द्र सिंह 3– अरविन्द कुमार बालिग 4– प्रवीन कुमार बालिग 5– राकेश कुमार सिंह बालिग 6– राजेश कुमार बालिग पुत्रगण शिवप्रसाद 7– राणाप्रताप बालिग पुत्र जितेन्द्र सिंह 8– श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह सभी निवासीगण ग्राम कलनाखोर, तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर –विपक्षीगण
तारीख पेशी 04–01–2027
को यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन ने संरक्षक/वारिस नियुक्त किए जाने के लिए यह आवेदन दिया है अतएव यह सूचना आपत्तिकर्ताओं को उपसंजाति और बाद की पेशी के प्रयोजन के लिए 04–01–2027 दिवस नियत करके निकाली जाती है कि यदि आपको/किसी अवधि के भीतर स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा 10:00 बजे पूर्वाहन के पूर्व न्यायालय के न्यायालय के उपसंजाति होकर अपनी आपत्ति पेश करें उक्त निर्णित अवधि के अवसान होने की दशा में आपकी किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और के आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया जायेगा। सन् 20 के के दिवस को दिनांकित।
द0 हाकिम

बैठक से गायब अफसरों का वेतन रोकें, विकास कार्य समय पर कराएं –जगदम्बिकापाल



संवाददाता–सिद्धार्थनगर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को लोहिया कला भवन में हुई। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चली बैठक में सांसद जगदंबिका पाल ने विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से आयोजित बैठक में बिजली, सड़क, पेयजल समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विद्युत विभाग को नए मजरों और टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जर्जर बिजली तार बदलने और जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत चल रहे सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे कराने को कहा। सांसद ने 8 जुलाई 2026 को हुई पिछली दिशा बैठक की कार्यवाही और उसमें दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की।

सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जिले में स्वीकृत होने वाली प्रत्येक सड़क और अन्य विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण के दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था, उनके शिलापट भी संबंधित कार्यस्थलों पर लगवाए जाएं। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने और लोगों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही ने तेतरी–सोहांस–लोटन मार्ग की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। सांसद ने एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत काला नमक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि किसानों को योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाया जाए, जिससे जिले के स्थानीय उत्पाद को बेहतर बाजार मिल सके।

सांसद ने जिलाधिकारी से सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों, जिससे सिद्धार्थनगर पिछड़े जनपदों की श्रेणी से निकलकर अग्रणी जिलों में शामिल हो सके। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अनुपस्थित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी बैठकों में इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को जिले में चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में मतदाता प्रतिशत कम है। ऐसे में अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म–6 भरवाने में सहयोग करें। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर जेंडर रेशियो में सुधार लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है। वर्ष 2011 के बाद जनगणना की प्रक्रिया हो रही है। सभी लोग स्वयं और दूसरों की स्वगणना कराने में सहयोग करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटने न पाए। बैठक में कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा, डुमरियागंज विधायक सैय्यदा खातून, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह मौजूद रहे।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com